



दक्षिण भारत राष्ट्रमत



தக்ஷிண பாரதத் ராஷ்டிரமத் | தினமணி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 'इंडि' गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर नीतीश कुमार का गोलमोल जवाब

6 अपनों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी

7 शाहिद कपूर की फिल्म देवा का फर्स्ट पोस्टर रिलीज

फर्स्ट टेक

भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल करने की संभावना तलाश रहा ईरान नई दिल्ली/भाषा। ईरान द्वारा भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति फिर से शुरू करने के तरीकों पर विचार किया जा रहा है। वह चाबहार बंदरगाह के जरिये पेट्रो-रसायन समेत समग्र कारोबार का विस्तार करने का इच्छुक है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। ईरानी अधिकारी ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि आपामी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में ईरान के प्रति व्यवहार पहले कार्यकाल की तरह रहने की संभावना नहीं है क्योंकि चीन के रणनीतिक ताकत बढ़ाने के साथ वैश्विक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। ईरानी कच्चे तेल की भारत को आपूर्ति दोबारा शुरू करने की कवालत करते हुए इस अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों को एक रास्ता खोजने की जरूरत है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस महीने तीन सर्वेक्षण शुरू करेगा नई दिल्ली/भाषा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) जनवरी में तीन सर्वेक्षण शुरू करेगा। इनमें सामाजिक उपभोग-स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण (जनवरी से दिसंबर 2025), व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण-दूरसंचार और आईसीटी कौशल (जनवरी से मार्च), और शिक्षा (अप्रैल से जून) शामिल हैं। यह एनएसओ का सर्वे का 80वां दौर है। अन्य सर्वेक्षण... निश्चित अवधि पर होने वाला श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) (जनवरी-दिसंबर) और अनिर्णित यानी कंपनी के रूप गठित नहीं हुए उद्यम पर वार्षिक सर्वेक्षण (जनवरी-दिसंबर 2025)... हैं।

भूकंप प्रभावित वानुअतु को पांच लाख डॉलर की सहायता देगा भारत नई दिल्ली/भाषा। भारत ने प्रशांत द्वीपीय देश वानुअतु को पिछले महीने आए 7.4 तीव्रता वाले भूकंप से हुई तबाही से निपटने में मदद के लिए बृहस्पतिवार को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। नई दिल्ली ने वानुअतु को इस मुश्किल समय में देश के लोगों को हर संभव सहायता देने की अपनी लक्ष्यता से अलग कर दिया। दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुअतु के तट के पास 17 दिसंबर को आए भूकंप से भारी तबाही और जान-माल की हानि हुई। विदेश मंत्रालय (एम्ईए) ने कहा, भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच के तहत एक करोड़ मित्र और साझेदार के रूप में तथा वानुअतु के मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में, भारत सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता प्रदान करती है।

03-01-2025 04-01-2025
सूर्योदय 5:54 बजे सूर्यास्त 6:32 बजे
BSE 79,943.71 (+1,436.30)
NSE 24,188.65 (+445.75)
सोना 80,014 ₹. (24 कैर) प्रति ग्राम
चांदी 100,000 ₹. प्रति किलो

निशान मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

केलाश मण्डेला, मो. 9828233434
शीत लहर
लो खत्म चुनावी गर्मी फिर, आई उत्तर से शीत लहर।
ठिठुरे जंगल, तड़पा, हर गांव-गांव व शहर-शहर।
भर डाला मौसम में कितना, किसने अमृत या तेज जहर।
परिणाम दिखायेंगे तब कहना, मेहर हुई या हुआ कहर।।

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने किया फैसला 15 प्रतिशत बढ़ेगा बस किराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बंगलूरु/भाषा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों के बस किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि जैसी परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा, "मंत्रिमंडल ने चार राज्य परिवहन निगमों- कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी), कल्याण कर्नाटक सड़क

केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी, केकेआरटीसी, बीएमटीसी के बस किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय



परिवहन निगम (केकेआरटीसी) और बंगलूरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) के बस किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय पांच जनवरी से लागू होगा। उन्होंने कहा कि बीएमटीसी का बस किराया 10 जनवरी, 2015 को बढ़ाया गया था जब डीजल की कीमत 60.90 रुपये प्रति लीटर थी। पाटिल ने बढ़ोतरी को उचित ठहराते हुए कहा, "चारों निगमों की रोजाना डीजल खपत 10 साल पहले 9.16 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 13.21 करोड़ रुपये हो गई है। इन चारों निगमों में कर्मचारियों पर प्रतिदिन 12.95 करोड़ रुपये का खर्च होता था, जो बढ़कर 18.36 करोड़ रुपये प्रतिदिन हो गया है। इसलिए संशोधन जरूरी था।"



2025 रक्षा सुधारों का वर्ष होगा:

उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा डीआरडीओ : राजनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बल में बदलने के उद्देश्य से भारत द्वारा 2025 को 'रक्षा सुधारों का वर्ष' घोषित करने के एक दिन बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि डीआरडीओ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सिंह ने यहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के मुख्यालय का दौरा किया और

इसके 67वें स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विभिन्न अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने डीआरडीओ से तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बेदाते हुए आगे बढ़ने और बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित किए जाने पर कहा कि डीआरडीओ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत ने बुधवार को 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया था और कहा था कि इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना तथा सेना को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है। रक्षा मंत्रालय ने जिन सुधारों की योजना बनाई है उनका व्यापक उद्देश्य रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना, बाधाओं को दूर करना, अक्षमताओं को समाप्त करना और संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना है।

40 साल बाद, भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीला कचरा निपटान के लिए ले जाया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

धर (मध्य प्रदेश)/भाषा। भोपाल गैस त्रासदी के चालीस साल बाद, बंद हो चुके यूनियन कार्बाइड कारखाने से 377 टन खतरनाक कचरे को निपटान के लिए धर जिले में स्थित पीथमपुर की एक इकाई में ले जाया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बुधवार रात करीब नौ बजे जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में 'ग्रीन कॉरिडोर' के जरिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धर जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया।



बुधवार रात करीब नौ बजे जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में 'ग्रीन कॉरिडोर' के जरिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धर जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया। धर के पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने पीटीआई-भाषा को फोन पर बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार सुबह करीब 4.30 बजे वाहन पीथमपुर स्थित एक फैंक्ट्री पहुंचे, जहां कचरे का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रक फिलहाल पीथमपुर स्थित फैंक्ट्री परिसर में खड़े हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बुधवार को बताया, धर जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र तक वाहनों की करीब सात घंटे की यात्रा के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। उन्होंने बताया कि रविवार से करीब 100 लोगों ने 30 मिनट की शिफ्ट में काम करके कचरे को पैक कर ट्रकों में रखा। सिंह ने बताया, उनकी स्वास्थ्य जांच की गई और हर

अनुच्छेद-370 ने कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोये : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि अनुच्छेद-370 ने कश्मीर के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोये और नरेन्द्र मोदी सरकार ने घाटी में न केवल आतंकवाद का, बल्कि आतंकवाद के पूरे ढांचे का भी खाल्ता कर दिया। शाह ने कहा कि अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35ए, दोनों को पांच अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये दोनों कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के रास्ते में प्रमुख बाधाएं थीं। कश्मीर के शेष भारत के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जो भू-सांस्कृतिक है और जिसकी सीमाएं

मोदी सरकार ने आतंकवाद का खात्मा किया



उसकी संस्कृति से बनती हैं। शाह ने यहां 'जम्मु एंड कश्मीर एंड लद्दाख : भू द एजेंस' नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि भारत को केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य से ही समझा जा सकता है, भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं। उन्होंने कहा कि 'सिलक रूट' से लेकर मध्य एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर हेमिस मठ तक; तथा व्यापार से लेकर अध्यात्म तक, दोनों का मजबूत आधार कश्मीर की संस्कृति में मौजूद है। शाह ने कहा कि अनुच्छेद-370 ने यह गलत धारणा दी कि कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण अस्थायी है। उन्होंने कहा, "कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अनुच्छेद-370 और आतंकवाद के बीच क्या संबंध है। वे नहीं जानते कि अनुच्छेद-370 ने घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोए थे।"

शाह ने कहा, "देश के कई अन्य हिस्सों में मुस्लिम आबादी है। वे क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित क्यों नहीं हैं?" गृहमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की सीमा के करीब है, इसलिए यहां समस्या आई। उन्होंने सवाल किया, "लेकिन गुजरात भी पाकिस्तान की सीमा के करीब है। राजस्थान भी पाकिस्तान की सीमा के करीब है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बना?" शाह ने कहा कि अनुच्छेद-370 ने यह गलत धारणा दी कि कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण अस्थायी है और इसने अलगाववाद के बीज बोये, जो बाद में आतंकवाद में बदल गए। गृहमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से कश्मीर में आतंकवाद के कारण 40,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने कश्मीर में न केवल आतंकवाद को, बल्कि आतंकवाद के ढांचे को भी खत्म किया।"

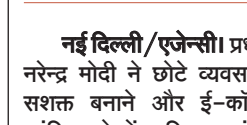
ब्रह्मपुत्र के जरिए चल रही है चीनी साजिश, जवाब दें मोदी : कांग्रेस

नई दिल्ली/एजेन्सी।

कांग्रेस ने कहा कि चीन भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रच रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे इस बांध के कारण चीन का नदी के बहाव पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। चीन इस बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ 'वाटर बम' की तरह कर सकेगा। पार्टी ने अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट किया चीन इस बांध के जरिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ ला सकता है। वहीं, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर, पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा कर सकता है और इससे वह पूर्वोत्तर राज्यों की सिंचाई और बिजली उत्पादन पर भी असर डाल सकेगा। कांग्रेस ने सवाल किया, मोदी सरकार इस गंभीर खतरे पर खामोश क्यों है।

ओएनडीसी से छोटे व्यवसायों को बल, ई-कॉमर्स में क्रांति : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com



नई दिल्ली/एजेन्सी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और ई-कॉमर्स में क्रांति लाने में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित खुले ऑनलाइन मंच- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) के योगदान का उत्सव करते हुए गुरुवार को कहा कि यह विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री पीयूष गोयल की ओएनडीसी के बारे में सोशल मीडिया मंच एक्स पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोदी ने लिखा, ओएनडीसी ने छोटे व्यवसायों को



रूप से छोटे उद्यमों को सशक्त भी बनाया है। विक्रेताओं और खरीदारों के बीच की खाई को पाटकर, ओएनडीसी देश के ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगातार क्रांति कर रहा है। वाणिज्य मंत्री ने ओएनडीसी की उपलब्धियों को एक पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित किया है जिसके अनुसार इस मंच पर इस छोटी अवधि में ही लेन-देन की संख्या 15 करोड़ हो गया है। इस खुले नेटवर्क से 200 से अधिक ई-कॉमर्स नेटवर्क जुड़ चुके हैं और इससे 600 से अधिक शहरों और कस्बों के सात लाख बिक्रेता तथा सेवा प्रदाता जुड़ चुके हैं। देश भर के 1100 से अधिक शहरों और कस्बों के ग्राहक ने इस ओएनडीसी के माध्यम से खरीदारी की है।

बधाई



उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें नये साल की शुभकामनाएं दीं। उपराष्ट्रपति सचिवालय के अनुवार धनखड़ राष्ट्रपति को नववर्ष की बधाई देने राष्ट्रपति भवन पहुंचे।

किसानों की उचित मांगों पर विचार क्यों नहीं कर सकता केंद्र : न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र से पूछा कि यह क्यों नहीं कर सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की उचित शिकायतों पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नई याचिका पर जवाब देने को

कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की पीठ ने पूछा, आपका मुकदमा यह बयान क्यों नहीं दे सकता कि वह वास्तविक मांगों पर विचार करेगा और हम किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं? केंद्र सरकार बयान क्यों नहीं दे सकती? इस पर मेहता ने कहा, शायद न्यायालय को विभिन्न कारकों की जानकारी नहीं है, इसलिए अभी हम खुद को एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के मुद्दे तक सीमित रख रहे हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक किसान के प्रति धिंतित है। डल्लेवाल की ओर से नई याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ता गुनिंदर कौर गिल से कहा गया कि वे टकराव वाला रुख न अपनाएं, क्योंकि अदालत ने ऐसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।

भारत-ईएफटीए समझौता 2025 खत्म होने से पहले लागू होने की उम्मीद : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साल का अंत होने से पहले लागू होने की उम्मीद है।

दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में भारत को समूह से 15 साल में 100 अरब डॉलर की निवेश

प्रतिबद्धता मिली है जबकि स्विस घड़ियों, चाँकलेट और कटे पॉलिश हीरे जैसे कई उत्पादों को कम या शुल्क पर अनुमति दी गई है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्यों में आइसलैंड, लीशटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

गोयल ने इस समझौते के इस साल लागू होने की संभावना के बारे में पूछे गए पीटीआई-भाषा के एक सवाल पर कहा, "हां, ईएफटीए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है और अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रीय परिषद के पास भेजा जाएगा।



ईएफटीए समूह के देशों को किसी व्यापार समझौते को अपनी-अपनी संसद से अनुमोदन लेना जरूरी होता है। उन्होंने कहा, "समझौते को स्विट्जरलैंड के राजनीतिक हलकों में भारी समर्थन मिलना वास्तव में आने वाले समय का संकेत है। यह दर्शाता है कि एक

महत्वपूर्ण बाधा पार हो गई है और उन्हें कैलेंडर वर्ष 2025 का अंत होने से पहले इस साल की शरद ऋतु तक इसे लागू करने की उम्मीद है।" अन्य देशों के साथ एफटीए वार्ता की प्रगति पर गोयल ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित समझौते पर वहां के नए

व्यापार मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस महीने के अंत में प्रस्तावित एफटीए पर अगले दौर की वार्ता होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एफटीए पर भी यूरोपीय व्यापार आयुक्त के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, "हम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ महीनों में जल्द ही फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं।" इसके साथ ही गोयल ने कहा कि भारत इन समझौतों में अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "जब तक समझौता न्यायसंगत, निष्पक्ष और संतुलित नहीं होगा, भारत किसी भी तर्कहीन शर्तों पर सहमत नहीं होगा।"



छात्रों ने हॉस्टल शौचालय में वीडियो रिकॉर्ड किये जाने का संदेह जताया, विरोध प्रदर्शन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। हैदराबाद के बाहरी उपनगर मेडचल स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में तब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जब कुछ छात्रों ने संदेह जताया कि छात्रावास के शौचालय में उनके वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यह जानकारी पुलिस से दी।

बुधवार रात और बृहस्पतिवार को कॉलेज परिसर में आयोजित प्रदर्शनों के दौरान विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य प्रदर्शनकारी

छात्रों में शामिल हुए। कुछ प्रदर्शनकारी कॉलेज के गेट पर लगे ताले को तोड़ने लगे, जबकि अन्य लोग गेट पर चढ़कर परिसर में घुसे। उन्होंने "हमें न्याय चाहिए" जैसे नारे लगाए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम कॉलेज पहुंची। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को मीडिया को बताया कि छात्रों ने संदेह जताया है कि लड़कियों के शौचालय में पहले भी वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर, संस्थान के प्रबंधन की ओर से कुछ लापरवाही पाई गई, क्योंकि

लड़कियों के छात्रावास के पीछे भ्रमिकों के कपरे बनाए गए थे। पुलिस ने कहा कि पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनके फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों के मोबाइल फोन की भी जांच की गई, लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला है। पुलिस ने कहा कि एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। कॉलेज के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें बुधवार को छात्रों से एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि किसी ने शौचालय की खिड़की से वीडियो बनाया है।

अधिकारी मंत्रालय में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें : देवेन्द्र फडणवीस

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे

दक्षिण मुंबई स्थित राज्य सचिवालय 'मंत्रालय' में एआई का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें। फडणवीस ने उन्हें मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। फडणवीस ने मंत्रालय में गृह विभाग और पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। एक अधिकारी ने बताया कि फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बैठक के दौरान 'मंत्रालय' में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मंत्रालय में सुरक्षा मजबूत करने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करें तथा प्रवेश द्वार से अंदर तक के लिए दोस (सुरक्षा) व्यवस्था विकसित करें। अधिकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी काम के सिलसिले में नियमित रूप से मंत्रालय से विधान भवन पास में स्थित विधानमंडल परिसर) जाते हैं। विधानमंडल सत्र के दौरान इन दोनों स्थानों पर आंगतुकों की संख्या काफी बढ़ जाती है। फडणवीस ने इसे देखते हुए उन्हें विशेष पास जारी करने का आदेश दिया।



हिमाचल 828 मेगावाट क्षमता की 22 नई पनबिजली परियोजनाएं आवांटी करेगा : सुखविंदर सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार 828 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 22 नई पनबिजली परियोजनाएं आवांटी करने के लिए तैयार है। ये परियोजनाएं कुलू, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला जिलों में स्थित हैं। इनकी क्षमता 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक होगी।

सुख्य ने कहा कि चिनाब नदी बेसिन के लिए 595 मेगावाट की कुल क्षमता वाली नौ परियोजनाओं का सबसे बड़ा आवांटी किया जाना है। इसके अलावा सतलज नदी बेसिन के लिए 169 मेगावाट की कुल आठ परियोजनाएं, रावी बेसिन के लिए 55 मेगावाट वाली चार परियोजनाएं और ब्यास बेसिन के लिए नौ मेगावाट की क्षमता वाली

एक परियोजना निर्धारित की गई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार पहली बार इन परियोजनाओं को अन्य राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय एवं राज्य उपक्रमों को आवांटी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "परियोजनाओं को 40 साल के पट्टे पर 10 लाख रुपए प्रति मेगावाट के अग्रिम प्रीमियम के साथ सौंपा जाएगा।" उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय राज्यों और केंद्रीय उपक्रमों के सचिवों को पहले ही एक पत्र जारी कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, मुफ्त बिजली के माध्यम से राउरच में वृद्धि होगी और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "इससे आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश को भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।"

दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल को विवादों को हमेशा के लिए सुलझाना चाहिए : उच्चतम न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवादों को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बनाई गई योजना के लिए धनराशि जारी किए जाने की जानकारी मिलने के बाद न्यायालय ने यह टिप्पणी की।

इस योजना के तहत लोगों को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे पीड़ितों के अस्पताल के बिल का भुगतान भी करती है। न्यायमूर्ति वी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब दिल्ली सरकार ने कहा कि शहर के अस्पतालों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा देने वाली उसकी योजना 'फरिश्ते दिल्ली के' की खातिर धनराशि मंजूरी कर दी गई है। अदालत दिल्ली सरकार की उस याचिका पर



सुनवाई कर रही थी जिसमें लंबित बिलों का भुगतान करने, निजी अस्पतालों को भुगतान जारी करके योजना को फिर से चालू करने और जानबूझकर इसे 'बंद' करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शदान फरासत ने पीठ को दिसंबर 2023 में शीर्ष अदालत द्वारा दिये गये नोटिस के बाद धनराशि जारी करने की जानकारी दी। पीठ ने कहा कि इस घटनाक्रम के मद्देनजर मामला सुलझ गया है और याचिका का निपटारा कर दिया गया। दिसंबर 2023 में, दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना के लिए धनराशि रोकने का आरोप लगाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल (पूज) कार्यालय और अन्य से जवाब मांगा था।

सेबी की जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के खिलाफ कार्यवाही जारी, फिर से कारण बताओ नोटिस जारी करेगा

नई दिल्ली/भाषा। बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सूचीबद्धता मानदंडों के कथित उल्लंघन को लेकर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. के खिलाफ जांच जारी रखे हुए है और इस मामले में संस्थापक चैयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनित गोयनका को नया कारण बताओ नोटिस भेजेगा।

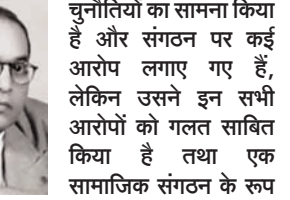
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के न्याय नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों ने पाठित आदेश में कहा है कि उन्हें जारी किए गए पहले कारण बताओ नोटिस (एससीएन) की बातों को भी नया नोटिस में शामिल किया जाएगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और उच्चतम न्यायालय को एक बयान के कथित शीर्ष प्रबंधक खुलासा नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सेबी की जांच के दायरे में है। उन्हें इससे पहले जुलाई, 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

डॉ. अंबेडकर 1940 में आरएसएस की शाखा में आर थे : विश्व संचार केंद्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नागपुर/भाषा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर 85 साल पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की एक शाखा में आए थे। संघ के मीडिया केंद्र विश्व संचार केंद्र (वीएसके) ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। वीएसके के विदर्भ प्रांत के बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर कहा कि अंबेडकर ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद वह आरएसएस को अपनेपन की भावना से देखते हैं।

बयान के मुताबिक, आरएसएस ने अपनी अब तक की यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया है और संघटन पर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसने इन सभी आरोपों को गलत साबित किया है तथा एक सामाजिक संगठन के रूप में अपनी पहचान को फिर से पुष्ट किया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस पर विभिन्न कारणों से तीन बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हर बार यह बेदाग निकला। बयान के अनुसार, आरएसएस पर दलित विरोधी होने के आरोप लगे और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर तथा आरएसएस के बारे में गलत सूचना फैलाई गई। लेकिन अब डॉ. अंबेडकर और आरएसएस के बारे में एक नया दस्तावेज सामने आया है, जो दोनों के बीच संबंधों को उजागर करता है।



चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के 15 दिन बाद 65 वर्षीय व्यक्ति घर वापस लौटा

कोल्हापुर/भाषा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के 15 दिन बाद एक व्यक्ति वापस घर लौट आया। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कसाबा-बावड़ा निवासी पांडुरंग उल्ले को 16

दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद उल्ले के पड़ोसी और रिश्तेदार उनके अंतिम

संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उल्ले की पत्नी ने कहा, जब हम उनके शव को अस्पताल से घर ला रहे थे, तो उस दौरान ही जब एम्बुलेंस एक स्पीड ब्रेकर से गुजरी और हमने देखा कि उनकी उंगलियों में हलचल हो रही है।

दिल्ली में बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैट कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैट में मदद करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पड़ोसी देश के दो नागरिक शामिल हैं जो कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में घुसे थे। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य दो लोगों पर बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैट कराने और दस्तावेज बनवाने में मदद करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य परिवहन का प्रबंधन और भारत में उनके रहने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद करते थे। पुलिस ने फर्जी आधार, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आवेदन और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

उम्मीद है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है, केंद्र जल्द राज्य का दर्जा बहाल करे : उमर



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है और केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी राज्य का दर्जा वापस पाना है। हम लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे किए गए वादे पूरे जाएंगे। सबसे बड़ा वादा राज्य का दर्जा बहाल करना है।

अब्दुल्ला ने यहां शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में मीडियाकर्तवियों से

बातचीत में कहा, उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा था कि राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। तब से एक वर्ष बीत चुका है और हमारा मानना है कि एक वर्ष काफी है। उन्होंने अपनी दो महीने पुरानी सरकार के समक्ष मौजूद विभिन्न मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करना होता है। अब्दुल्ला ने कहा, हमें सत्ता में आए दो महीने से थोड़ा अधिक समय हो गया है। हमें यह समझने में समय लगा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार कैसे काम करती है। हम पहले भी सरकार चला चुके हैं, लेकिन उस स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में बहुत अंतर है।

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। जम्मू-कश्मीर में सीमित शक्तियां वाली विधानसभा है, जबकि दूसरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं है। दिसंबर 2023 में, उच्चतम न्यायालय ने विशेष दर्जा रद्द करने और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि वह जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे।



नार साल में बड़े पैमाने पर वृद्धि हासिल करने का भरोसा: महिंद्रा समूह सीईओ

नई दिल्ली/भाषा। महिंद्रा समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक अनिशा शाह ने नए साल में समूह के आगे बढ़ने का भरोसा जताते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

शाह ने समूह के कर्मचारियों को भेजे गए साल के अपने संदेश में कहा है कि पिछले एक साल में समूह ने अपनी वृद्धि को तेज किया है और इसके व्यवसाय महत्वाकांक्षी राह पर अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम बड़े पैमाने पर वृद्धि हासिल करने की अपनी आकांक्षा से प्रेरित होकर उम्मीद और विश्वास के साथ आगे देखते हैं। हम एक मकसद के साथ नेतृत्व करना जारी रखेंगे, साहसिक लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें पाने के लिए अनुशासन एवं दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे।" शाह ने वर्ष 2024 को सभी आयामों में अविश्वसनीय साल बताने हुए कहा कि इस दौरान समूह का प्रदर्शन साहसिक लक्ष्यों से भी ऊंचे आगे निकल गया। उन्होंने इसका श्रेय महिंद्रा की टीम को देते हुए कहा कि अपनी मौजूदगी वाले हरेक क्षेत्र में समूह सार्थक भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा, "हमारे पास वाहन, कृषि और सेवाओं में एक संतुलित पोर्टफोलियो है और हमने एक अच्चा संतुलन हासिल किया है। प्रत्येक खंड हमारी समग्र लाभप्रदता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।"

प्रधानमंत्री के 'नए साल के संकल्प' लोगों का जीवन बर्बाद करने वाले जुमलों से कम नहीं: कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने निजी खपत में गिरावट, महंगाई, 'आर्थिक असमानता' को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि उनके "नए साल के संकल्प" लोगों का जीवन बर्बाद करने वाले जुमलों से कम नहीं हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार के पास आर्थिक उथल-पुथल का कोई समाधान नहीं है। खरगे ने 'एक' पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार के पास खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक उथल-पुथल का कोई समाधान नहीं है। कुछ संकेतक साफ बताते हैं कि आम भारतीयों के जीवन में कितनी समस्या है। गोल्ड लोन में 50 प्रतिशत की वृद्धि और गोल्ड लोन एनपीए में 30 प्रतिशत का उछाल आया।" उन्होंने दावा किया कि निजी खपत कम हो गई है तथा कारों की बिक्री में वृद्धि चार साल के निचले स्तर पर आ गई है।

उनका कहना था, "पिछले 5 वर्षों (2019-2023) में इंजीनियरिंग, विनिर्माण, प्रक्रिया



और बुनियादी ढांचे (ईएमपीआई) के क्षेत्र में मजदूरी केवल 0.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ी। पिछली आठ तिमाहियों में नवंबर में यूपीआई लेनदेन की खाद्य मुद्रास्फीति औसत 7.1 प्रतिशत रही है। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष कराधान से घरेलू बचत घट रही है जो 50 साल के निचले स्तर पर है।"

खरगे के अनुसार, घरेलू वित्तीय देनदारियां अब सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत हैं, जो दशकों में सबसे अधिक है। उन्होंने दावा किया, "रूपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे विदेशी धन बाहर चला गया और छोटे निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।" कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "नरेन्द्र मोदी जी, आपके वार्षिक 'नए साल के संकल्प' प्रत्येक नागरिक के जीवन को नष्ट करने वाले जुमलों से कम नहीं हैं।"

यूपीआई के जशिये लेनदेन दिसंबर में आठ प्रतिशत बढ़कर 16.73 अरब पर

नई दिल्ली/भाषा। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से लेनदेन की संख्या दिसंबर में मासिक आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 16.73 अरब तक पहुंच गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। नवंबर में यूपीआई लेनदेन की संख्या 15.48 अरब थी।

एनपीसीआई ने कहा कि लेनदेन का मूल्य दिसंबर, 2024 में 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि नवंबर में यह 21.55 लाख करोड़ रुपए था। दिसंबर के दौरान औसत दैनिक लेनदेन संख्या 53.97 करोड़ रही, जो नवंबर में 51.1 करोड़ थी। मूल्य के संदर्भ में, दिसंबर में औसत दैनिक लेनदेन 74,990 करोड़ रुपए रहा। वहीं नवंबर में यह 71,840 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ की पहल एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए प्रमुख इकाई है। एनपीसीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का संचालन करता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। एक नया साइबर घोटाला सामने आया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं, गृहणियों, छात्रों और जुरातों लोगों को निशाना बनाया जाता है और वे प्रतिदिन बड़ी रकम गंवा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। रिपोर्ट के अनुसार, इसे पिग बुचरिंग स्कैम या 'निवेश घोटाला' के रूप में जाना जाने वाला यह घोटाला एक वैश्विक मामला है और इसमें बड़े पैमाने पर धन शोधन और यहां तक कि 'साइबर स्लेवरी' भी शामिल है।



लक्षित विज्ञापन के लिए एक आसान सुविधा प्रदान करता है। 'पिग बुचरिंग स्कैम' या 'निवेश घोटाला' के रूप में जाना जाने वाला यह घोटाला एक वैश्विक मामला है और इसमें बड़े पैमाने पर धन शोधन और यहां तक कि 'साइबर स्लेवरी' भी शामिल है।

माना जाता है कि 2016 में चीन में शुरू हुआ 'पिग बुचरिंग स्कैम' भोले-भाले व्यक्तियों को निशाना बनाता है, जिनका साइबर अपराधी समय के साथ भरोसा जीतते हैं और अंततः उन्हें क्रिप्टोकॉर्सेसी या किसी अन्य आकर्षक योजना में निवेश करने के लिए राजी कर लेते हैं और

फिर उनकी रकम चोरी कर लेते हैं। 'पिग बुचरिंग' की उपमा सूअरों को मारे जाने से पहले उन्हें खिला पिलाकर मोटा किये जाने से आई है। इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने समय-समय पर तत्काल कार्रवाई के लिए खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने के वारंटे गूगल के साथ साझेदारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधी भारत में अवैध रूप से ऋण देने वाले ऐप शुरू करने के लिए प्रायोजित फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कहा गया, ऐसे लिक की सक्रिय रूप से पहचान की जाती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें फेसबुक तथा फेसबुक पेजों के साथ साझा किया जाता है।

जद (एस) नेता सूरज रेवन्ना ने हासन के लोगों का ऋण चुकाने का संकल्प लिया

हासन/दक्षिण भारत। जनता दल (सेक्युलर) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सूरज रेवन्ना ने कहा है कि वह और उनके छोटे भाई प्रज्ज्वल रेवन्ना हासन के लोगों का ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और विधायक एच डी रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को गौड़ा परिवार और जद (एस) कार्यकर्ताओं को परेशान करने के खिलाफ नेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती। सूरज ने बुधवार शाम को हासन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सूरज अकेले नहीं उगाता। यह चमकने और रोशनी (प्रज्ज्वल) लाने के लिए उगाता है। आपके प्रज्ज्वल अन्ना और सूरज अन्ना हासन के लोगों का ऋण चुकाएंगे। सूरज और उनके भाई एवं पूर्व सांसद प्रज्ज्वल यौन उन्नीयन के मामलों का सामना कर रहे हैं। प्रज्ज्वल कथित यौन उन्नीयन के मामले में जेल में हैं, जबकि अपराधिक यौन उन्नीयन के आरोपों का सामना कर रहे सूरज जमानत पर बाहर हैं। सूरज ने कहा, 'हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ अधिकारी और हमारे विरोधी हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई भी सरकार स्थायी नहीं है।'

मंत्री प्रियंक खरगे ने ठेकेदार आत्महत्या मामले से उन्हें जोड़ने पर भाजपा की आलोचना की

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने ठेकेदार सचिन पांचाल आत्महत्या मामले से उनका नाम जोड़े जाने के लिए बृहस्पतिवार को भाजपा नेताओं की आलोचना की और कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंक ने कहा कि सचिन पांचाल और संतोष पाटिल के आत्महत्या मामले पूरी तरह से अलग हैं। संतोष पाटिल ने 12 अप्रैल, 2022 को उडुपी के एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। प्रियंक ने कहा, संतोष पाटिल ने स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का उल्लेख किया था, जबकि पांचाल मामले में सुसाइड नोट में मेरा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा एक निराधार मुद्दा उठा रही है। उन्होंने पूछा, 'क्या भाजपा ने पाटिल के परिजनों को मुआवजा दिया या उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी?' मंत्री ने यह भी कहा कि बलात्कार और जातिवादी टिप्पणी के मामलों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री मुनिरत्न को अभी तक भाजपा से निष्कासित नहीं किया गया है, जिससे पार्टी की अपने नारे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के प्रति गंभीरता पर संदेह पैदा होता है। सिविल ठेकेदार सचिन पांचाल ने 26 दिसंबर को बीदर जिले में चलती ट्रे के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पांचाल ने अपने सुसाइड नोट में प्रियंक खरगे के करीबी राजू कपनूर पर उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तेलुगू अभिनेत्री कोल्ला हेमा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मई 2024 में बेंगलूरु में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पास एक रेव पार्टी में कथित तौर पर मादक पदार्थ के इस्तेमाल के मामले में तेलुगू अभिनेत्री कोल्ला हेमा के खिलाफ कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर ने 52 वर्षीय हेमा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश दिया। याचिका में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दायर आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक अदालत चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई पुनः शुरू नहीं कर देती। मंगलवार को अदालत का फैसला हेमा के वकील की दलीलों के बाद आया, जिन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 (बी) के तहत आरोप (मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित) एक सह-आरोपी के कब्जानामे पर आधारित थे। वकील ने तर्क दिया कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि हेमा ने किसी प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था। बेंगलूरु की 'सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी)' द्वारा रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि पार्टी में शामिल कई लोगों के रक्त के नमूनों में मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप पत्र में हेमा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एमडीएम नामक मादक पदार्थ का सेवन किया था।

बाइक शोरूम में आग लगने से 52 मोटरसाइकिल जलकर स्वाहा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। महादेवपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बी. नारायणपुरा में एक मोटरसाइकिल शोरूम में बुधवार को रात आग लगने से शोरूम में रखी नई मोटर साइकिलों सहित कुल 52 मोटरसाइकिल जलकर स्वाहा हो गईं। जानकारी के अनुसार बुधवार को शाम सात बजे जब शोरूम के संचालक यमाहा शोरूम को बंद करके घर बने गए और ड्यूटी पर तैनात सिक्युरिटी गार्ड रात्रि 8 बजे के समय भोजन के लिए चला गया। इस दरम्यान शो रूम से धुंआ दिखाई दिया तो रात्रि 8.40 बजे लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी। फायर ब्रिगेड वाहनों ने मौके पर आकर आग पर काबू किया लेकिन तब तक कुल 52 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई थीं। शोरूम के पीछे यमाहा का सर्विस स्टेशन भी है जिसको भी आग से नुकसान पहुंचा है।

नग्मा मेट्रो में महिला की फोटो खींचने पर कार्रवाई

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। नग्मा मेट्रो से यात्रा करने वाली एक साफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि यात्रा के दौरान उसकी किसी ने फोटो खींची है जिसपर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर को मेट्रो से मैजैस्टिक से जेपीनगर की ओर जाते समय महिला साफ्टवेयर इंजीनियर ने जयनगर मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी को बताया कि उसकी बिना अनुमति के एक व्यक्ति ने फोटो खींची है। जयनगर के सुरक्षाकर्मी ने उस व्यक्ति से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार पेशे से आर्ग्युमेंट डॉक्टर के फोन में उस महिला की फोटो मिली जिसे डिलीट करवाया गया और लिखित माफीनामा के बाद उसे हिरासत देकर छोड़ दिया गया।

खेल रत्न के लिए चुने गए गुकेश का मविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने का वादा

चेन्नई/नई दिल्ली। शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश ने गुरुवार को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद मविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने का वादा किया।

निमिषा प्रिया : रिश्तेदारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अभी भी क्षमादान मिलने की उम्मीद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

कोवि/भाषा। यमन के एक नागरिक की हत्या करने के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के परिवार के सदस्यों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अभी भी उसे माफी मिलने की उम्मीद है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने प्रिया की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि कर दी है। प्रिया इस अपराध के लिए 2017 से यमन की जेल में बंद है। 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' के सदस्य बाबू जॉन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, यदि पीड़िता तलाल अब्दो महदी का परिवार 'ब्लड मनी' स्वीकार करने और निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए सहमत हो जाए, तो उसकी जान बच सकती है। हम आशावादी हैं, लेकिन केंद्र सरकार से तत्काल सहायता मिलना बहुत जरूरी है। 'ब्लड मनी' एक अपराधी या उसके परिवार द्वारा पीड़ित के परिवार को दिया जाने वाला पैसा या किसी प्रकार का मुआवजा है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लोण्डे की रहने वाली निमिषा प्रिया को यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में कथित तौर पर मौत की सजा दी गई है। खबरों के अनुसार प्रिया को 2020 में एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में फैसले को

श्रीलंका ने रिहा किए 20 भारतीय मछुआरे, स्वदेश लौटे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

चेन्नई। श्रीलंका की जेलों से रिहा किए गए 20 भारतीय मछुआरे विमान से चेन्नई पहुंच गए हैं। मछुआरों को एक साल पहले श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। वे तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम और तूत्तुकुडी जिलों के निवासी हैं और श्रीलंका की जेलों में थे। भारत और श्रीलंका सरकार के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका ने 20 मछुआरों को रिहा कर दिया। उन्हें भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके बाद मछुआरों को कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे पर ले जाया गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मछुआरों को नागरिकता सत्यापन, सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा। इसके बाद मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अलग-अलग वाहनों से उनके गृहनगर पहुंचाने की व्यवस्था की। ज्ञात हो कि तमिलनाडु के मछुआरा संघ राज्य के मछुआरों की नियमित गिरफ्तारी के बाद तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे हस्तक्षेप करें और बीच समुद्र में मशीनी नावों की जल्दी और गिरफ्तारी को रोकें, जो मछुआरों की आजीविका की रीढ़ हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में इस मुद्दे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। पीएमके अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुगिण रामदास ने भी भारतीय मछुआरों की ओर अधिक गिरफ्तारियां रोकने के लिए केंद्र से कड़े हस्तक्षेप की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के 504 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई अधिकारियों की हिरासत में हैं। करीब 48 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावें भी श्रीलंकाई अधिकारियों के कब्जे में हैं।

खेल रत्न के लिए चुने गए गुकेश का मविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने का वादा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

गुकेश हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने जब उन्होंने चीन के डिंग लिरेंग को हराया। वह विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। गुकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके 'एक्स' पर लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर वास्तव में आभारी हूँ और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। आपके शब्दों और मार्गदर्शन ने मुझे हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया है।' उन्होंने अपनी इस पोस्ट में खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी टैग करते हुए लिखा, 'वादा करता हूँ की शतरंज की बिसात और उसके बाहर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखूंगा। आपके निरंतर समर्थन के लिए माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को धन्यवाद। गुकेश को निशानेबाज मनु भाकर, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा-पथलोट प्रवीण कुमार के साथ देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए चुना गया है।

उच्च न्यायालय ने एस वी शेखर को दी गई सजा को बरकरार रखा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एस वी शेखर को एक विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई एक माह की साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा। शेखर को यह सजा अपने सोशल मीडिया पेज पर महिला पत्रकारों पर अपमानजनक पोस्ट साझा करने के लिए सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति पी वेलमुगुन ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए शेखर द्वारा दाखिल की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में शेखर ने विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था। सांसदों और विधायकों से संबंधित विशेष अदालत ने पिछले फरवरी में अभिनेता-राजनेता को दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी। शेखर ने 19 अप्रैल, 2018 को सोशल मीडिया मंच पर महिला पत्रकारों के बारे में एक पोस्ट साझा की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। 'तमिलनाडु जर्नलिस्ट्स एंड प्रोटेक्शन एसोसिएशन' द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सिटी पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था।

पिनरई विजयन का सनातन धर्म पर बयान बिल्कुल स्पष्ट : माकपा राज्य सचिव गोविंदन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की केरल इकाई के सचिव एमवी गोविंदन ने बृहस्पतिवार को कहा कि समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को 'सनातन धर्म' से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो 'चतुर्वर्ण्य' प्रणाली पर आधारित है। गोविंदन ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की उस टिप्पणी का समर्थन किया कि 'एक जाति, एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर' का उपदेश देने वाले गुरु को सनातन धर्म के समर्थक के रूप में चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, शिवगिरी तीर्थयात्रा के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री का दिया बयान स्पष्ट है और सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। माकपा नेता ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन के बुधवार को शिवगिरी में दिए गए भाषण की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का बयान सनातन धर्म के अधिकार को केवल (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) परिवार को सौंपने के समान है। गोविंदन ने आरोप लगाया, सतीशन सनातन धर्म पर भाजपा-संघ के कुतर्कों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंदन ने कहा कि भाजपा-आरएसएस गठबंधन गुरु के आदर्शों को सनातन धर्म के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जो 'चतुर्वर्ण्य' व्यवस्था पर आधारित है। उन्होंने कहा, उनका (भाजपा-आरएसएस) अंतिम मकसद संविधान को बदलना और उस प्रणाली के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाना है। सतीशन ने कहा था कि सनातन धर्म 'केवल वर्ण' व्यवस्था के बारे में नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसमें अद्वैत, तत्वमसि, वेद और उपनिषद शामिल हैं और यह अवधारणा संघ परिवार का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सतीशन ने कहा था कि सनातन धर्म 'केवल वर्ण' व्यवस्था के बारे में नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसमें अद्वैत, तत्वमसि, वेद और उपनिषद शामिल हैं और यह अवधारणा संघ परिवार का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए।

एनएसएस महासचिव नायर ने मंदिर में रीति-रिवाजों में बदलाव का समर्थन करने के लिए विजयन की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

कोट्टायम/भाषा। नायर सर्विस सोसाइटी (एनएसएस) के महासचिव जी सुकुमारन नायर ने मंदिर में रीति-रिवाजों में बदलाव का समर्थन करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बृहस्पतिवार को आलोचना की। विजयन ने एक मठ के प्रमुख स्वामी के उस आह्वान का समर्थन किया है, जिसमें राज्य के मंदिरों में प्रवेश करने से पहले पुरुष श्रद्धालुओं को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने की आवश्यकता संबंधी मौजूदा प्रथा को देवरवम बोर्ड समाप्त करने की योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री और शिवगिरी मठ के रुक की आलोचना करते हुए नायर ने कहा, ईसाई और मुसलमानों के भी अपने रीति-रिवाज हैं। क्या मुख्यमंत्री या शिवगिरी मठ में उनकी लंबे समय से जारी प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई है। नायर ने छह साल पहले सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंदिर की अपनी परंपराएं होती हैं जिन्हें न तो सरकार और न ही कोई व्यक्ति बदल सकता है। उन्होंने यह बयान चंगनारसेरी में एनएसएस मुख्यालय में मन्नाथु कुमारी ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह मेरी अंतिम अपील है। उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। एक्शन काउंसिल के हर सदस्य जनता से एक वीडियो संदेश में प्रेमा कुमारी ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह मेरी अंतिम अपील है। उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। एक्शन काउंसिल के हर सदस्य ने धन जुटाने के लिए अथक प्रयास किया है। केंद्र और काउंसिल से विनती करती हूँ कि उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।



चेन्नई पोर्ट ने नए कीर्तिमान स्थापित किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

स्थापित 1,70,606 मिमी टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष, आईएसएस सुनील पालीवाल ने इन उपलब्धियों में विभिन्न योगदानकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने टर्मिनल ऑपरेटर मेसर्स चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ हितधारकों और बंदरगाह अधिकारियों के बहुमूल्य कार्य को स्वीकार किया।

चेन्नई। चेन्नई पोर्ट ने 5.326 मिलियन मीट्रिक टन के मासिक ट्रैफिक को संभाला है, जो 15 वर्षों में पहली बार इस मील के पथर तक पहुंच गया है। इसके अलावा, चेन्नई पोर्ट ने दिसंबर 2024 में 1,80,686 टीईयूएस (ट्रेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) को संभालकर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हासिल किया है, जो अगस्त 2024 में

टीवीएस मोटर कंपनी की दिसंबर में कुल बिक्री सात प्रतिशत बढ़कर 3,21,687 इकाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी की दिसंबर, 2024 में कुल बिक्री सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़कर 3,21,687 इकाई हो गई। दिसंबर, 2023 में कंपनी ने 3,01,898 वाहन बेचे थे। कंपनी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा, पिछले महीने कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री आठ प्रतिशत बढ़कर 3,12,002 इकाई हो गई, जबकि दिसंबर, 2023 में यह 2,90,064 इकाई थी। घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री दिसंबर, 2024 में मामूली रूप से बढ़कर 2,15,075 इकाई हो गई, जो दिसंबर, 2023 में 2,14,988 इकाई थी। कंपनी के अनुसार, पिछले महीने उसकी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 79 प्रतिशत बढ़कर 20,171 इकाई हो गई, जबकि दिसंबर, 2023 में यह 11,288 इकाई थी। दिसंबर, 2023 के 11,834 इकाइयों की तुलना में पिछले महीने तिपहिया वाहनों की बिक्री कम होकर 9,685 इकाई रह गई। बयान में कहा गया, पिछले महीने निर्यात 22 प्रतिशत बढ़कर 1,04,393 इकाई हो गया, जो पिछले साल समान महीने में 85,391 इकाई था।

सुंदरम फाइनेंस ने शतरंज टूर्नामेंट हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

चेन्नई। वित्तीय व्यवसाय में कार्यरत सुंदरम फाइनेंस ने मैलापुर महोत्सव के अंतर्गत 15 वें शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 11 एवं 12 जनवरी को करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यह कार्यक्रम शिवा स्वामी अय्यर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैलापुर में आयोजित किया जाएगा।

SUNDARAM FINANCE
Enduring values. New age thinking.

जिसमें 12 वर्ष आयु तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक बच्चे email : scorpcomm@gmail.com पर रजिस्ट्रर कर सकते हैं।



युवा 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं : बागडे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने युवाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत के सुदृढ़ 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बागडे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लातूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59 वें देवगिरी राज्य सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश की जीडीपी में लगभग 34 प्रतिशत योगदान युवाओं का है। एबीवीपी 'राष्ट्र प्रथम'

की भावना के साथ राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ने की पहल करें। उन्होंने इस संगठन के जरिए गांव और शहर का भेद मिटाते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास' से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सब मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने विचारों और ऊर्जा का योगदान राष्ट्र की समृद्धि करते हुए देते हैं तो निश्चित ही अच्छे परिणाम सामने आएं। बागडे ने कहा कि भारत की

सांस्कृतिक जड़ों को खोजला करने के लिए मैकाले द्वारा देश की शिक्षा पद्धति को बदला गया। होना तो यह चाहिए था कि देश में 15 अगस्त, 1947 को जिस तरह से झंडा बदला गया था वैसे ही शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम आज भी इसका परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1986 में जो शिक्षा नीति बनी, उसके 34 वर्ष बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण ऐतिहासिक पहल है। इसमें भारतीयता को सर्वोच्च महत्व दिया गया। यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है।

यह स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा के साथ आधुनिक सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर इसे तैयार करने की चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि इस संगठन की बरतारज माधवजी की पहल पर इसलिए स्थापना हुई कि इससे राष्ट्रीयता के लिए कार्य किया जा सके। उन्होंने देवगिरी राज्य सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताया।

कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप जारी

जयपुर। राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी और कोहरा का प्रकोप बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, राज्य में कुछ स्थानों पर बृहस्पतिवार को घना कोहरा छाया रहा। केन्द्र के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में श्रीगंगानगर में 5.3 डिग्री, चूरु में 5.4 डिग्री, बीकानेर और चूरु में 5.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी जयपुर में बृहस्पतिवार सुबह 7.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अन्य सभी प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया।

माफी काफी नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



जयपुर। मणिपुर में जातीय संघर्ष के लिए पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा 'माफी' मांगे जाने के एक दिन बाद बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है, अगर वह मानते हैं कि स्थिति को संभालने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा के साथ आधुनिक सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर इसे तैयार करने की चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि इस संगठन की बरतारज माधवजी की पहल पर इसलिए स्थापना हुई कि इससे राष्ट्रीयता के लिए कार्य किया जा सके। उन्होंने देवगिरी राज्य सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताया।

से 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सिंह ने इंकाल में संवाददाताओं से कहा था, 'राज्य में जो कुछ हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। कई लोगों ने अपना कोश दिया और कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं खेद व्यक्त करता हूँ और माफी मांगता हूँ। लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में अपेक्षाकृत शांति देखने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो हुआ सो हुआ... मैं सभी समुदायों से माफ करने की अपील करना चाहता हूँ और पिछली गलतियों को भूल जाओ। शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर में एक साथ रहकर नए सिरों से जीवन शुरू करें। गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री 18 माह के खून-खराबे के बाद अब माफी मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर वह स्थिति को संभालने में नाकाम रहे थे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए

यरेलू विवाद में पत्नी का सिर फोड़ा, मौत

जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गंगपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को यरेलू विवाद के बाद पति ने कथित तौर पर पत्नी के सिर पर भारी चीज से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। गंगपुर के पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र प्रताप ने बताया कि घटना झुमपुरा गांव में बुधवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे की है और आरोपी बद्रीलाल (45) को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि महिला प्रेम देवी (42) के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है। परिजनों के यहां पहुंचने पर बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम करवाया जायेगा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

इधर-उधर की बात ना करें अशोक गहलोत, ये बताएं खुद का कारवां क्यों लुटा? : अग्रवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



जयपुर। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राममोहन दास अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार को नकारा-निकम्मी कहने, मणिपुर के सीएम के यहां की हिंसा पर माफी मांगने को लेकर दिए बयान पर कहा कि जनता उनको चुनना नहीं पहले ही बता चुकी है, कि सरकार किसकी नकारा-निकम्मी थी। अग्रवाल ने बुधवार को यहां प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में गहलोत के सरकार को नकारा-निकम्मी कहने, मणिपुर के सीएम के यहां की हिंसा पर माफी मांगने को लेकर दिए बयान पर कहा कि जनता उनको चुनना नहीं पहले ही बता चुकी है, कि सरकार किसकी नकारा-निकम्मी थी। गहलोत पर भी मौजूद रहे। संगठन चुनावों के

प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया ने अब तक हुए संगठन चुनावों की जानकारी दी। अग्रवाल ने समय पर चुनाव पूरे करने के निर्देश दिए। राठौड़ ने प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में आगामी निकाय चुनावों की भी चर्चा हुई है। अग्रवाल ने इसकी अभी से रणनीति बनाकर जीत के लिए काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले एक साल में जो क्रांतिकारी कार्य किए हैं, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए। राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित किए। अपराध पर अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान किया। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करने का ऐतिहासिक कार्य हुआ। तय है कि अगले विधानसभा चुनावों में भी भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी।

उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आईटी की रेड : फीस में टैक्स चोरी पर कार्रवाई, छात्रों को वलासेस से बाहर निकाला

जयपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर शुक्रवार को आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टैक्स चोरी के आरोपों के चलते जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, इंदौर और अन्य स्थानों पर एक साथ आयकर विभाग की टीमों ने रेड डाली। छापेमारी के दौरान सेंट्स पर क्लासेज चल रही थीं। जैसे ही आयकर टीमों ने संस्थानों में प्रवेश किया, छात्रों और स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। टीमों ने तत्काल छात्रों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया और पूरे परिसर को कब्जे में ले लिया। छापेमारी के दौरान किसी भी अग्रिम घटना से बचने के लिए संस्थानों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने फीस से संबंधित दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार, उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर फीस के माध्यम से टैक्स चोरी करने का आरोप है। आयकर विभाग इस बात की पड़ताल कर रहा है कि संस्थान ने अपनी आय का पूरा विवरण सरकार को दिया था या नहीं। इस कार्रवाई के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कई अभिभावक इस बात को लेकर घिंतित हैं कि इस घटना का छात्रों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा।



केकड़ी जिला समाप्ति के विरोध में बार एसोसिएशन का आंदोलन, मुंडन करवाकर निकाली आक्रोश रैली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

केकड़ी। केकड़ी जिले को समाप्त करने के विरोध में गुरुवार को जिला यथावत रखने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। इसके तहत शहर में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान कोर्ट परिसर में केकड़ी जिला रद्द करने के विरोध में शहर के नौ युवकों ने सिर के बाल कटाकर मुंडन कराकर सरकार के फैसले के खिलाफ तीव्र आक्रोश प्रकट किया। सुबह बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। जहां से वे नारेबाजी करते हुए तीन बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, पंटाघर, सदर बाजार, सरसडी गेट, बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय

पहुंचे और केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर प्रशिक्षु आरएस श्रद्धा सिंह को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि केकड़ी जिला भौगोलिक व हर दृष्टि से जिले के मापदंड पूरा करता है। केकड़ी को जिला बने करीब 17 महीने का समय हो गया है। यहां पर सभी तरह के जिला कार्यालय सरकारी भवनों में ही संचालित थे। लोगों को जिला स्तरीय सुविधाएं मिलना शुरू हो गई थी। लोगों के काम आसानी से हो रहे थे। इसके बावजूद केकड़ी जिले को सरकार ने हटा दिया। यह सरकार का जन विरोधी फैसला है। ज्ञापन में बताया कि डींग, सलूंवर, कोटपूतली-बहरोड सहित कई छोटे जिले ऐसे हैं, जिनको सरकार ने बरकरार रखा है। जबकि

केकड़ी जिले को हटाकर केकड़ी के लोगों के साथ अन्याय किया है। ज्ञापन के माध्यम से केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा सहित सैकड़ों पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद थे। रैली सम्पन्न होने के बाद कोर्ट परिसर में सरकार के फैसले के विरोध में कई युवाओं ने मुंडन कराया। मुंडन कराने वालों में सुरेंद्र चौधरी, एडवोकेट शिव प्रकाश चौधरी, राहुल राव, जोधाराम जाट, किसान मोर्चा के अध्यक्ष ग्राम आलोली के धर्मराज मीणा, आलोली के रंगलाल मीणा, किशनलाल चौधरी, ग्राम काली तलाई का खेड़ा के हेमराज चौधरी एवं ग्राम कुमावतों का नगमाव के हंसराज कुमावत शामिल हैं।

निजी बस नें दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को टक्कर मारी

जयपुर। राजस्थान के दोसा जिले में बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे व पर एक निजी बस ने पहले से आपस में टकराए दो ट्रकों को टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार करीब 45 यात्री घायल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक चारुल गुना ने बताया कि घने कोहरा के चलते उज्जैन से दिल्ली जा रही श्रद्धालुआ की बस पहले से दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों से जा टकराई जिससे बस में सवार करीब 45 यात्री घायल हो गए। उन्होंने बताया कि 20 से अधिक घायलों को दोसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं चार गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया।



कांग्रेस की मजबूत जड़ों के कारण जुड़ रहे कार्यकर्ता, सरकार को मिलकर चेताएं : तिवाड़ी

जयपुर। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक पीसीसी मुख्यालय में हुई। जयपुर जिलाध्यक्ष आरआर तिवाड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ साल भर चलाई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा हुई। बैठक में जयपुर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, सभी 8 विधानसभा के ब्लॉक, वार्ड और मंडल अध्यक्ष सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तिवाड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की अभी देश में 3 राज्यों में ही सरकार बची है, लेकिन कांग्रेस की जड़ें आज भी इतनी मजबूत हैं कि कार्यकर्ता पार्टी में जुड़कर काम करना चाहता है। भाजपा सरकार के आते ही लोग कांग्रेस को इस आस के साथ देखने लगे हैं कि उनकी पीड़ा के लिए हम संघर्ष करेंगे। भाजपा सरकार में लोगों का जीना दूभर हो गया है। पुरानी

जनकल्याणकारी योजनाएं बंद करने की कोशिश की जा रही है। मंहगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कानून व्यवस्था लचर हो गयी है। एक साल में बिना कोई उपलब्धि वाली सरकार के पास जनता की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। इनके मंत्री विधायक आपस में ही लड़ रहे और खुद के काम नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं, तो जनता के काम कैसे होंगे।

पटवारी 8 हजार रुपये रिश्तव लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

अजमेर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये मुकेश चौधरी पटवारी, पटवार हल्का सनोदिया, तहसील सरयवाड़ा, जिला अजमेर को परियादी से 8 हजार रुपये रिश्त राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की हैल्पलाईन नं० 1064 पर परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज में आरोपी मुकेश चौधरी पटवारी द्वारा 10 हजार रुपये रिश्त राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी की अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचन्द के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया आरोपी मुकेश चौधरी पटवारी को परियादी से 8 हजार रुपये की रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।



'भारतीय संविधान: भारत की आत्मा' विषय पर व्याख्यान सत्र और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। शांति एवं अहिंसा निदेशालय और बियानी लॉ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान के अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को 'भारतीय संविधान : भारत की आत्मा' विषय पर व्याख्यान सत्र और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैवा ने दीप प्रज्वलित कर की। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैवा ने संविधान के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा संविधान न्याय, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों को सुनिश्चित करता है। उन्होंने नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों पर भी बल दिया और कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान में निहित मूल्यों का पालन करे। उन्होंने

कहा कि संविधान हमें समानता, भाईचारे और आपसी सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जो एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की नींव है। सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने भारत माता के जयकारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं के संविधान निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने विचार स्वतंत्र रूप से समाज के सामने व्यक्त कर सके। सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि कई लोग संविधान के अधिकार प्राप्त होने के बावजूद इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं रखते और उसका उचित सम्मान नहीं करते। उन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया और पौधरोपण को प्रोत्साहित करने की बात कही। शांति एवं अहिंसा विभाग के शासन सचिव वी. सरवन कुमार ने संविधान पढ़ने और उसे समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें न केवल हमारे अधिकारों

और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक अजय असवाल ने संविधान और महात्मा गांधी के विचारों के बीच अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत दस्तावेज बनाने में प्रेरणा दी। बियानी युप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉ. संजय बियानी ने महात्मा गांधी के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि शांति और अहिंसा हमारे जीवन के मूलभूत मूल्य हैं। कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान सत्र और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों में संविधान के दौरान व्याख्यान सत्र और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों में संविधान के दौरान व्याख्यान सत्र और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में दो टीमों के समान अंक आने पर टाई ब्रेकर के माध्यम से विजेता का निर्णय किया गया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बंगाल को अस्थिर करने के इरादे से घुसपैटियों को भारत में घुसने दे रही है बीएसएफ : ममता का आरोप



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

को भारत में घुसने दे रहा है। यह राज्य को अस्थिर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। इसमें केंद्र सरकार की गहरी साजिश शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें बीएसएफ के इस रवैये के पीछे केंद्र का ब्लूप्रिंट नजर आ रहा है।

बनर्जी ने कहा, गुंडे भारत में घुस रहे हैं। मैं सीमा के दोनों तरफ शांति चाहती हूँ। पड़ोसी बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रियो ने आरोप लगाया कि बीएसएफ द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से पूछा, वे (बीएसएफ) महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन अपने विरोध क्यों नहीं किया? बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा, सीमाओं की रखवाली हमारे हाथ में नहीं है। खसाली हमारे काम है। तृणमूल कांग्रेस सीमा की रखवाली नहीं करती। जब लोग घुसते हैं तो वे कहा जा रहे हैं? डीएफ को जानकारी होती है कि वे कहा जा रहे हैं।

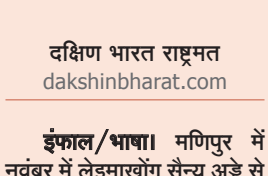
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बीएसएफ पर लगाये गये आरोपों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

करते हुए 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि राज्य की 'असफल' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कदर 'भ्रम' में हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा, 'सीमा पर निगरानी के लिए चौकियाँ स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध न कराने के बावजूद वह अवैध घुसपैठ के लिए सीमा सुरक्षा बल को दोषी ठहराती रहती हैं। लेकिन अब उन्होंने आरोपों की सभी हदें पार करके हुए अपने ही प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है।' मजूमदार ने आरोप लगाया कि बनर्जी के अनुसार, उनके प्रशासन के तहत 'अक्षम' जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक विदेशी अपराधियों को उनकी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्या करने के लिए सीमा पर घुसपैठ करने की अनुमति दे रहे हैं। भाजपा नेता ने पूछा, 'अब तक वे इस तरह की घटनाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती थीं। लेकिन ममता बनर्जी के बयान में अचानक यह बदलाव क्यों आया? क्या वे ऐसे दावे करके अपनी पार्टी के लुटेरे, अपराधी प्रतिनिधियों के कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं?'

मणिपुर : सैन्य अड़े से लापता हुए व्यक्ति के घर के बाहर हथगोला मिला



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

यह भी लिखा था, जमीन की बिक्री करने वाला कोई भी ठेकेदार जेएसी का हिस्सा नहीं हो सकता। जेएसी 25 नवंबर को सिंह के लापता होने के बाद से जारी विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री उम बिरें सिंह ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि सिंह सैन्य अड़े से लापता हो गया। उन्होंने कहा था कि मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, असम के कछार जिले का मूल निवासी सिंह 57वीं माउंटन डिवीजन के लीमाखोंग सैन्य अड़े में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एनईएस) के साथ काम करने वाले एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षण था। पुलिस ने पहले कहा था कि मेडती समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिंह की तलाश के लिए 2,000 से अधिक सुरक्षाकर्मीयों को तैनात किया गया है।

त्रिपुरा में शिक्षक-छात्र अनुपात में 'बड़े अंतर' को दूर किया जाएगा: साहा



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

अगरतला/भाषा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश सरकार विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात में 'बड़े अंतर' को दूर करेगी।

मुख्यमंत्री ने गोमती जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को ठीक से लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए परिकल्पित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। (त्रिपुरा में) शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक बड़ा अंतर रहा है। कई विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। मैंने इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा और वित्त विभागों के सहियों से बात की है। शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभाल रहे साहा ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, पहले हम पश्चिम बंगाल बोर्ड और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पढ़ाते थे, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक अध्ययन करना पड़ता था। अब यह समस्या दूर हो गई है। सरकार ने पहले ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, वर्तमान में राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एमबीबी विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के अलावा छह निजी विश्वविद्यालय हैं। अब राज्य के बाहर से भी छात्र यहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। साहा ने नौवीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित किए जाने की पहल को भी रेखांकित किया। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग ने पिछले साल नौवीं कक्षा की छात्राओं के बीच 1.30 लाख साइकिलें बांटी हैं। एक छात्र के लिए साइकिल बहुत मायने रखती है, जिससे वह आसानी से स्कूल जा सकती है।

बिहार : 'इंडि' गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर नीतीश कुमार का गोलमोल जवाब



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के विपक्षी गठबंधन 'इंडि' में वापस आने के प्रस्ताव पर गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, क्या बोल रहे हैं। राजभवन में नये राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कुमार से जब लालू प्रसाद के नये प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, 'क्या बोल रहे हैं'। खान और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ खड़े कुमार से जब यह पूछा गया कि क्या राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, तो नवनियुक्त राज्यपाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, इस तरह के सवाल पूछने का यह सही समय नहीं है। आज खुशी का दिन है। हमें सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। पिछले एक दशक के दौरान कुमार दो बार विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दल राजद के साथ गठबंधन कर चुके हैं। वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव की टिप्पणियों पर सफाई देते हुए दावा किया कि राजद सुप्रियो ने केवल मीडिया की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। लालू प्रसाद ने एक टीवी चैनल से कहा था, हमारे दरवाजे (नीतीश के लिए) खुले हैं। उन्हें भी अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। इससे दोनों तरफ के लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। राजभवन में नए राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए यादव ने कहा, मैंने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

एक हजार करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में बंगाल में आठ स्थान पर ईडी की छापेमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल में आठ स्थानों पर छापेमारी की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट, साल्ट लेक और बागुइहाटी इलाकों में पांच जगहों और विभिन्न जिलों में तीन अन्य स्थानों पर एक साथ शुरू की गई छापेमारी जारी है। अधिकारी ने कहा कि साल्ट लेक इलाके में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, हमारे अधिकारी अब बागुइहाटी में एक उच्च श्रेणी के आवासीय परिसर के एक फ्लैट पर छापेमारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के राज्यों के कई लोग अपराध में शामिल पाए गए हैं।

आगरा में नकली धी बनाने वाली फैक्टरी पर छापा, 18 ब्रांड के 'लेबल' मिले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

पुलिस को ताजगंज के शमसाबाद रोड के कहरई मोड़ स्थित इस अस्थायी फैक्टरी से भारी मात्रा में अमूल ब्रांड के नकली धी की मेचर के लिए आपूर्ति होने की सूचना मिली थी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी)-सिटी सूरज राय ने संवाददाताओं को बताया कि फैक्टरी में अमूल सहित कई नामचीन ब्रांड का नकली धी तैयार किया जा रहा था। फैक्टरी से 18 ब्रांड के 'लेबल' मिले हैं जिनमें धी भरकर उसकी आपूर्ति की जाती थी। फैक्टरी से धी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा यूरिया और कई अन्य रसायन सहित अन्य सामान भी मिला है।

देश के 440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरा: रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जबकि 3.55 प्रतिशत नमूनों में 'आसन्निक' संदूषण पाया गया। मई 2023 में भूजल की गुणवत्ता की जांच के लिए देश भर में कुल 15,259 निगरानी स्थानों को चुना गया। इनमें से 25 प्रतिशत कुओं (बीआईएस 10500 के अनुसार बरबसे अधिक जोखिम वाले) का विस्तार से अध्ययन किया गया। पुनर्भरण से गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी लेने के लिए मानसून से पहले और बाद में 4,982 स्थानों से भूजल का नमूना लिया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि जल के 20 प्रतिशत नमूनों में नाइट्रेट की सांद्रता 45 मिलीग्राम प्रति लीटर (एमपी/एल) की सीमा को पार कर गई, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित है। 'वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट-2024' से यह भी पता चला कि 9.04 प्रतिशत नमूनों में 'फ्लोराइड' का स्तर भी सुरक्षित सीमा से अधिक था, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रेट सीमा से ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र के नमूनों में संदूषण 35.74 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.48 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 23.5 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 22.58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का प्रतिशत कम पाया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे।

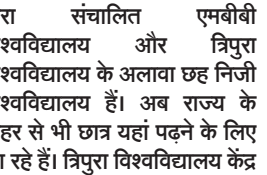
रोहित पर गिर सकती है गाज, गंभीर ने कप्तान की अंतिम एकादश में जगह की नहीं की पुष्टि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

पर फंसला करेंगे। गंभीर के इस कैप्शन जवाब ने उन अटकलों को और हवा दी जिनके अनुसार कप्तान रोहित शर्मा की खराब फॉर्म के कारण अंतिम एकादश में जगह पकड़ी नहीं है। कुछ ही घंटों में यह बात लगभग पक्की हो गई कि 37 वर्षीय रोहित ऐसे पहले भारतीय कप्तान बनें वहां हैं जिन्हें खराब फॉर्म के कारण हटाया जाएगा। और यह सब एक पंक्ति के जवाब से शुरू हुआ। गंभीर के जवाब से यह लगभग स्पष्ट हो जाता है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान दौर में अपना अंतिम मैच खेल चुके हैं। वह अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाए थे। रोहित जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तभी से यह अतिरिक्त उछाल और सीम मूवमेंट का सामना नहीं कर पाने के अलावा अपनी कप्तानी को लेकर आलोचना झेल रहे हैं। अब जबकि भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है तब एक टेस्ट क्रिकेट के रूप में रोहित का करियर निराशाजनक अंत की तरफ बढ़ रहा है। मेलबर्न की तरह ही यहां रोहित नेट्स पर अभ्यास के लिये आखिर में उतरें। अगर उन्हें बाहर किया जाता है तो इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे क्योंकि अभी तक वह पांच पारियों में केवल 31 रन बना पाए हैं। जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर वह सही साबित होती हैं तो फिर तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में ही पहला टेस्ट मैच जीता था। बुमराह ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है तथा 20 से भी कम आंसर से 30 विकेट लिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी और अनिल कुंबले ने मुंबला के बीच में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था क्योंकि उनका शरीर पांच दिनी क्रिकेट और खेल पाने की इजाजत नहीं दे पा रहा था।



ओडिशा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने की घोषणा की

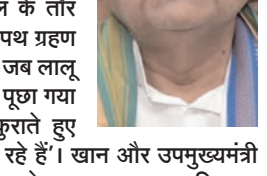


दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार उनकी पेंशन राशि में वृद्धि करेगी। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद किया गया था उनको अब 10,000 रुपए प्रति माह की जगह 20,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मिसा) के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को अब 20,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।

माझी ने कहा कि 21 महीने के आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोग अब 20,000 रुपए मासिक पेंशन के पात्र होंगे।

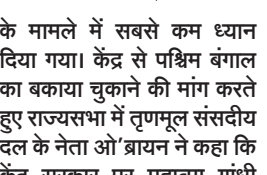
सहारनपुर में रेल पटरी पर धातु का टुकड़ा, कानपुर में खाली गैस सिलेंडर रखा मिला



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

सहारनपुर/कानपुर (उम)। कानपुर में बरजपुर रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर पांच किलोग्राम वाला एक खाली एलपीजी गैस सिलेंडर रखा मिला। यह जानकारी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बृहस्पतिवार को दी। एक अन्य घटना में मंगलवार को सहारनपुर जिले में हरिद्वार रेल लाइन पर टपरी के पास रेल पटरी पर रखे लोहे के एक बड़े टुकड़े का समय रहते पाया जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। एक सुरक्षा दल को बुधवार को गश्त के दौरान कानपुर के शिवराजपुर में लूपलाइन पटरी पर सिलेंडर मिला। अधिकारियों ने बताया कि सिलेंडर एक बोरे में रखा हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) अभिषेक वर्मा ने बताया, 'सूचना मिलने पर जीआरपी अधिकारी कानपुर और उसके पड़ोसी जिलों की फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके एवं सिलेंडर का निरीक्षण किया, जिसमें सिलेंडर खाली मिला।' उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांचकारी से पता चलता है कि सिलेंडर को जानबूझकर दहशत फैलाने के इरादे से पटरी पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच करने और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने भी मंगलवार तड़के पटरी पर लोहे का टुकड़ा मिला कि सिलेंडर एक बोरे में रखा हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई।

बिहार : प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

पटना/भाषा। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में आयोजित बिहार लोक सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन शुरू किया। किशोर ने पटना के गांधी मैदान में यह घोषणा की। गांधी मैदान उस स्थान से कुछ किलोमीटर दूर है जहां कई पीड़ित उम्मीदवार लगभग दो सप्ताह से चौबीसों घंटे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किशोर ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी मांगों में परीक्षा रद्द करना और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करना शामिल है। उन्होंने कहा 'मैं उन प्रश्न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करता हूँ, जिन्होंने कश्चित तौर पर परीक्षाओं द्वारा भरे जाने वाले पदों को खरीद-फरोखत के लिए रखा है।' उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात के तुरंत बाद, किशोर ने सोमवार को कहा था कि वह '48 घंटे' तक इंतजार करेंगे और अगर नीतीश कुमार सरकार 13 दिनों के भीतर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही, तो आंदोलन तेज हो जाएगा।

राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रेट सीमा से ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र के नमूनों में संदूषण 35.74 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.48 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 23.5 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 22.58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का प्रतिशत कम पाया गया।

अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रेट सीमा से ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र के नमूनों में संदूषण 35.74 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.48 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 23.5 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 22.58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का प्रतिशत कम पाया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे।

राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रेट सीमा से ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र के नमूनों में संदूषण 35.74 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.48 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 23.5 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 22.58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का प्रतिशत कम पाया गया।

अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रेट सीमा से ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र के नमूनों में संदूषण 35.74 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.48 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 23.5 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 22.58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का प्रतिशत कम पाया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे।

सुविचार

जैसे तुम ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, वैसे ही उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर से दूसरों का दोष देखना बंद हो जाए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

राष्ट्रीय सुरक्षा: मतभेदों से ऊपर उठें

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए बीएसएफ के बारे में जो बयान दिया है, वह हकीकत से कौनों दूर है। बीएसएफ के जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान दिए हैं। उन्होंने तो अनगिनत बार घुसपैठियों को खदेड़ा है। अगर बीएसएफ की ओर से सख्ती न की जाती तो घुसपैठियों के हांसले बहुत बुलंद होते। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बीएसएफ की काफी कोशिशों के बावजूद कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में दाखिल हो जाते हैं। भारत की बांग्लादेश के साथ लगती सीमा भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। वहां एक जैसा इलाका नहीं है। नदी, घने जंगल और दलदल वाले इलाके में यह संभव नहीं है कि हर कदम पर बीएसएफ अपना जवान खड़ा कर दे। तकनीकी विकास के साथ कुछ नए उपकरण जरूर आ गए हैं, लेकिन भौगोलिक चुनौतियां अपनी जगह बरकरार हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए किसी एक रास्ते से नहीं आते। अगर ऐसा होता तो इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता था। ये घुसपैठिए दबे पांव, रंगकर और कई तरीकों से दाखिल होने की कोशिशें करते हैं। ये महिलाओं और बच्चों को 'ढाल की तरह' इस्तेमाल करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो खुद को गरीब और जरूरतमंद बताते हैं। हो सकता है कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में दिया गया उनका बयान सही हो, लेकिन इस आधार पर किसी को भारत में अवैध ढंग से दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के साथ लगती सीमा से कोई घुसपैठिया दाखिल होने की कोशिश करे तो पहले उसे चेतावनी दी जाती है। वह फिर भी आगे बढ़ना जारी रखे तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'उचित कार्रवाई' की जाती है।

अगर बीएसएफ बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर भी उसी तर्ज पर कार्रवाई करनी शुरू कर दे तो कई नेता भारी हंगामा खड़ा कर देंगे, मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएंगे और पूरी कार्रवाई को ही संदेह के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया 'इधर आने' की कोशिश करता है तो बीएसएफ को उसकी पकड़-धकड़ करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश यह बचकर निकलने में कामयाब हो जाए तो संबंधित राज्य सरकारों को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए, जिससे वह गिरफ्त में आ जाए। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर सरकारी मशीनरी सुझबुझ के साथ इच्छाशक्ति रखते हुए काम करे तो घुसपैठियों पर काबू पाया जा सकता है। हाल में ऐसी खबरें सामने आई थीं, जिनमें बताया गया कि घुसपैठियों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समेत जरूरी दस्तावेज पाए गए हैं। कोई व्यक्ति इतने दस्तावेज बनवा सकता है तो वह मतदाता सूची में नाम भी जुड़वा सकता है! क्या ये अवैध कृत्य 'स्थानीय मददगारों' के बिना हो सकते हैं? क्या संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे ऐसे लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें? सरकारों को चाहिए कि वे बीएसएफ के साथ समन्वय रखते हुए ऐसा मजबूत तंत्र बनाएं, जिससे घुसपैठियों पर नजर रखने, उन्हें हिरासत में लेने में आसानी हो। जब कोई बांग्लादेशी अपने देश में रहकर यह खबर पढ़ेगा कि भारत में वरिष्ठ नेता ही बीएसएफ की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ खास इलाकों से घुसपैठ कराना तुलनात्मक रूप से आसान है तो उसका मन घुसपैठ करने के लिए क्यों नहीं मचलेगा? होना तो यह चाहिए कि वरिष्ठ नेता स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दें कि 'कोई व्यक्ति घुसपैठ के दौरान बीएसएफ की नजरों से बचकर हमारे यहां आ गया तो ऐसा बिल्कुल न समझे कि हम उसे बख्श देंगे और उसके लिए सुख-सुविधाएं जुटाएंगे ... हम घुसपैठियों को जेल भेजेंगे ... जो उनकी मदद करेगा, उसकी सजा और ज्यादा सख्त होगी।' जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए।

ट्विटर टॉक

संसदीय क्षेत्र कोटा स्थित एमबीएस और जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल प्रशासन को इमरजेंसी सेवाओं में सुधार करने, पुराने भवन के रिनोवेशन और परिसर में अनुपयोगी स्थानों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

-ओम बिरला

सिक्किम राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री ओम माथुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि जनसेवा के आपके सभी संकल्प सिद्ध हों, प्रभु आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन प्रदान करें।

-भजनलाल शर्मा

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल बीमा कंपनियों के जेब भरने की योजना बनकर रह गई है। किसान लगातार शिकायत करने आते हैं कि 2-3 साल पुराने फसल खराबे के क्लेम नहीं मिल रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसके संबंध में निवेदन किया।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

पुरुषार्थ से ताजगी

एक व्यक्ति अपने बचपन के साथी के पुत्र रामजी के यहां आया। रामजी ने अपने पिता के मित्र का स्वागत-सत्कार किया और उन्हें भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही भोजन का एक कौर मुंह में रखा तो वे बोले, 'बेटा! यह भोजन तो बासी है।' रामजी बोला, 'यह भोजन तो अभी बनाकर आपको परोसा गया, फिर आप इसे बासी कैसे कह रहे हैं?' बुढ़ बोले, 'बेटा! मेरे मित्र ने कितने कष्ट से पैसा कमाया। उन्होंने गुजरे एक वर्ष ही बीता है, इसी बीच तुमने आधी संपत्ति उड़ा दी, अब आगे क्या करोगे? तुम अपने परिश्रम से कमाये धन से भोजन बनवाते तो मैं उसे ताजा कहता।' रामजी की समझ में उनकी बात आ गई। उसने कहा, 'मैं शायदपूर्वक कहता हूँ कि अब मैं श्रम करके धन कमाऊंगा और उसी से अपना व परिवार का पालन-पोषण करूंगा।'

सामयिक

अपनों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी

रमेश सराफ धमोरा
मोबाइल : 9414255034

कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने ही साथी दलों के निशाने पर है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के संयुक्त इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वापस लेने की मांग की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की सुप्रियोम ममता बनर्जी खुले आम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेता पर से हटाने की मांग की है। ममता बनर्जी की मांग के समर्थन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रियोम लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी सहमति जताई है। इससे इंडिया गठबंधन की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है।

जून 2023 में 26 विपक्षी दलों के साथ बना इंडिया गठबंधन अब टूट के कगार पर खड़ा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई पराजय ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस के सहयोगी दल ही उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर अलग राह पकड़ने के संकेत दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाने तक की धमकी दे दी है। कांग्रेस द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद से ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से खासी नाराज नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उससे भाजपा को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन व संदीप दीक्षित के बयान विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा के कहने पर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्वेग बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद पवार), नेशनल काँग्रेस तो खुलकर कांग्रेस की मुखालफत करने लगी है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत तय मानकर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़कर 1.8 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। जबकि हरियाणा में कांग्रेस को 39.34 प्रतिशत वोट व भाजपा को 39.94 प्रतिशत वोट मिले थे। यदि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़ती तो निश्चय ही सरकार बन सकती थी। मगर कांग्रेस ने अवरस गवा दिया और



वहां भाजपा ने आसानी से तीसरी बार पहले से भी अधिक बहुमत से सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। जबकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर ही लड़ा था।

महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की करारी हार होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप और समाजवादी पार्टी को सीट ना देकर गलती की थी। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी लिखा गया कि कांग्रेस नेताओं के अति आत्मविश्वास और घमंड ने हरियाणा में हार के लिए भूमिका निभाई। पार्टी नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को लगने लगा था कि वह अकेले ही जीत सकती है। इसलिए किसी को भी सत्ता में भागीदार बनाना उचित नहीं समझा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस कुल 329 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिसमें से 145 सीटों पर बिना किसी गठबंधन की अकेले चुनाव लड़ी थी। जिसमें कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव जीती थी। कांग्रेस का बिना किसी दल से गठबंधन में जीत का रेशियो 25.52 प्रतिशत रहा था। जबकि कांग्रेस 184 सीटों पर साथी दलों से

गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इसमें कांग्रेस ने 62 सीट जीती थी और जीत का रेशियो 33.75 प्रतिशत रहा था। इस तरह से देखें तो कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की बजाय गठबंधन साथियों की बढौलत बड़ी जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख 59 हजार 64 यानी 21.29 प्रतिशत वोट मिले थे। गठबंधन करने के कारण 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस को 1.91 प्रतिशत अधिक वोट मिले थे।

कांग्रेस पार्टी ने पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में अपने बूते चुनाव लड़ा था। जबकि बिहार, गुजरात हरियाणा झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अंडमान निकोबार दीप समूह, आंध्र प्रदेश, दादरा नगर हवेली व दमन दीव, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड ऐसे प्रदेश हैं जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा जहां उनकी सीटें 44 से घटकर 16 रह गईं। महाराष्ट्र

कांग्रेस को यदि इंडिया गठबंधन को बचाना है तो अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों की भावनाओं को समझ कर फैसला करना होगा। तभी कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को बचा पाएगी। इंडिया गठबंधन टूटने की स्थिति में कांग्रेस का भी कमजोर होना तय माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अकेले भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती है। गठबंधन के साथी दलों की मदद से ही कांग्रेस मजबूत हो सकेगी इस बात से कांग्रेस नेता भी अच्छे से वाकिफ है।

नजरिया



परीक्षा शिक्षा का एक अहम पड़ाव है। इसे एक चुनौती के स्तर पर लें। चुनौती को जब हम हंसी-खुशी से स्वीकारते हैं, तब यह उत्सव और खेल बन जाती है। तनाव से मुक्त होकर, उत्साह और आत्मविश्वास की ऊर्जा से भरकर जब परीक्षा दी जाती है, तो हमें कई अप्रत्याशित खुशियों के खजाने मिल सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगा, हाई स्कूल में अंग्रेजी की मेरी तैयारी अच्छी थी। पहला पेपर बहुत शानदार हुआ था। सेकंड पेपर वाले दिन मैं आत्मविश्वास और उत्साह से भरा हुआ परीक्षा कक्ष में पहुंचा था।

आ रही परीक्षा की घड़ी

की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

खैर...अभी जब बोर्ड परीक्षाएं सामने हैं तो यह समय खेल-कूद, गणपथ, मोबाइल से दूरी बनाकर परीक्षा की तैयारी में लगाने का है। अभिभावकों के लिए भी नेक सलाह है कि वह बच्चे पर अपनी आपेक्षाओं का दबाव न बनाएं, बल्कि उसे भरपूर आर्थिक दबाव से मुक्त रखें। पढ़ाई जो होनी थी वो चुकी है। बस बचे हुए समय में प्रत्येक विषय के पहले पाठ को विधित पढ़ डालना है। यह आपकी पूरी पढ़ाई को सबल बनाएगा। कुछ प्रश्न और पेटेंट सिलेबस में बड़े महत्व के होते हैं। यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं और यह मार्क्स स्कोर करने में मददगार होते हैं। इनको समझने के लिए पुराने पेपरों की मदद ली जा सकती है। क्रेडन बैंक की पुस्तक में भी इस विषय में उपयोगी सामग्री मिल जाती है। अनुभवी अध्यापक भी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची उपलब्ध कराते हैं। पुराने एजाम पेपर की मदद से इस प्रकार के सवालों को समझना और हल करना परीक्षा के अन्तिम दिनों की तैयारी को इंपोर्टेंट चैप्टर और प्रश्नों की दिशा में केंद्रित कर देती है।

पढ़ाई के समय जो नोट बनाया जाता है, उसके महत्वपूर्ण अंशों को हाईलाइट कर फोल्ड करके और उसे अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। दीर्घउत्तरीय प्रश्नों की भूमिका में यदि समस्त मुख्य बिंदु समाहित हों तो परीक्षक अच्छे अंक देते हैं। हाईलाइट किए गए बिंदु इस सिलसिले में बड़ी सहायता करते हैं। परीक्षा मूलतः छात्रों की योग्यता की जांच का उपकरण है। इसलिए सवालों के जवाब अच्छी तरह देना एक परीक्षार्थी का धर्म होता है।

इन आखिरी दिनों में लिखने की प्रैक्टिस के साथ पाठों का रिवीजन किया जाए, तो यह परीक्षा कक्ष में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अक्सर परीक्षार्थी इस बात का अफसोस करते देखे जाते हैं कि प्रश्नोत्तर याद रहते हुए भी समय की कमी के कारण वह उसे लिख नहीं पाए। इससे बचने का प्रामाणिक तरीका है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को असल परीक्षा की तरह तीन घंटों के अन्दर हल करने का अभ्यास किया जाए। विशेषज्ञों का मत है कि इस अभ्यास के बीच अगर बोल-बोलकर लिखा जाए तो यह बहुत कारगर होगा। क्योंकि इससे आँख, हाथ, मस्तिष्क, मूँह, कान के बीच एक स्वाभाविक लय बन जाती है, जो परीक्षा के बीच एकफासता बनाए रखने में कारगर भूमिका निभाती है। प्रतिदिन एक या दो पुराने प्रश्नपत्रों को तीन घण्टों में हल करने का अभ्यास किया जाए। मात्र पाँच-छह प्रश्नपत्रों के हल करने की प्रक्रिया में समय और लिखने की गति पर ठीक-ठाक नियंत्रण हो जाएगा।

परीक्षा शिक्षा का एक अहम पड़ाव है। इसे एक चुनौती के स्तर पर लें। चुनौती को जब हम हंसी-खुशी से स्वीकारते हैं, तब यह उत्सव और खेल बन जाती है। तनाव से मुक्त होकर, उत्साह और आत्मविश्वास की ऊर्जा से भरकर जब परीक्षा दी जाती है, तो हमें कई अप्रत्याशित खुशियों के खजाने मिल सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगा, हाई स्कूल में अंग्रेजी की मेरी तैयारी अच्छी थी। पहला पेपर बहुत शानदार हुआ था। सेकंड पेपर वाले दिन मैं आत्मविश्वास और उत्साह से भरा हुआ परीक्षा कक्ष में पहुंचा था। किन्तु पेपर के शुरूआती तीन प्रश्न पढ़ते हुए पेपर के कठिन होने

में कांग्रेस शिवसेना (यूबीटी) व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद पवार) के साथ महाविकास अघाड़ी बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी। वहां कांग्रेस सबसे अधिक 101 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसमें महज 16 सीट ही जीत पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80 लाख 20 हजार 921 वोट मिले जो कुल मतदान का 12.42 प्रतिशत था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 15.38 प्रतिशत ही रहा। संसद का शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है। जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस ने अदानी मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दी। इससे संसद का कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। इसको लेकर भी कांग्रेस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, सपा ने कांग्रेस को घेरते हुये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बहस नहीं होने देना चाहती है तथा सिर्फ अदानी मुद्दे को ही ज़िंदा रखे हुए है। यदि संसद चलती तो कई तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता था।

इंडिया अलायंस में जिस तरह की खटपट वर्तमान समय में चलने लगी है वह अलायंस के लिए शुभ नहीं मानी जा सकती है। अलायंस में शामिल दल ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व को नकारने लगे हैं इससे बुरी बात कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। वही गठबंधन अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां भाजपा चुनाव जीतने की पूरी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वह दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज हो। मगर कांग्रेस का रवैया देखकर आम आदमी पार्टी भी सकते में है। पार्टी के नेता कांग्रेस को वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं तथा खुले आम भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को दो सूची जारी कर दी है। शेष सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। यदि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी पराजित हो जाती है तो इंडिया गठबंधन के ताबूत में वह आखिरी कील साबित होगी।

कांग्रेस को यदि इंडिया गठबंधन को बचाना है तो अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों की भावनाओं को समझ कर फैसला करना होगा। तभी कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को बचा पाएगी। इंडिया गठबंधन टूटने की स्थिति में कांग्रेस का भी कमजोर होना तय माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अकेले भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती है। गठबंधन के साथी दलों की मदद से ही कांग्रेस मजबूत हो सकेगी इस बात से कांग्रेस नेता भी अच्छे से वाकिफ है।



खराब सामग्री से निर्मित सड़क चार महीने में उखड़ी

माधावरम व आसपास के निवासी हो रहे हैं परेशान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के माधावरम से आंध्रप्रदेश के तड़ु तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 अपने निर्माण के चार महीने के उपरांत ही अंतिम सांस गिनने को मजबूर हो गया है। इस सड़क के किनारे बसे प्रवासियों द्वारा विगत वर्ष में की गई कई शिकायतों के उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जैसे तैसे राष्ट्रीय राजमार्ग-16 की मरम्मत लो की परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि

राष्ट्रीय राजमार्ग अपने निर्माण के चार महीने के उपरांत ही पुनः अपनी बहलाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण में घटिया रस्तर के मटेरियल का प्रयोग किया गया जिसके कारण कम समय में ही सड़क पुनः खराब हो गई।

स्थानीय निवासी तथा भारतीय जनता पार्टी के सरकारी संपाग के जिला सचिव एस अशोक मोदी ने दुख व्यक्त किया और सरकार से अनुरोध किया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल कर ताकि

आसपास रहने वाले निवासियों ने अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि गड्डे युक्त सड़कों पर चलना जोखिम भरा है बारिश के दिनों में तो स्थिति और बदतर हो जाती है। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण जाम की समस्या भी यहां हमेशा बनी रहती है जिससे बच्चों को प्रतिदिन स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है। देरी से पहुंचना पड़ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग के बहलाल स्थिति के कारण इस इलाके के प्रवासियों को अनगिनत समस्याओं से हर दिन जूझना पड़ रहा है।

डॉ विजय गुरु द्वारा नव कुण्डीय सहस्रचण्डी यज्ञ 5 से होगा प्रारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय श्री विधा शक्ति सर्वरम संस्था के तत्वावधान में डा विजयगुरुजी के सान्निध्य में अम्बा यज्ञ होने जा रहा है इस अम्बा यज्ञ में ललिताम्बा का शस्त्र चण्डी यज्ञ होगा। जिसमें उत्तरभारत के करीब 151 वैदिक ब्राह्मणों 9 दिन तक आहुति देंगे। डा विजयगुरुजी ने बताया कि अतिवाक्य के दरसास रोड स्थित ललिताम्बा कुंज में 5 जनवरी से प्रारंभ होने वाले यज्ञ स्थल पर श्रीविधा शक्ति सर्वरम में



गोशाला, वैदिक गुरुकुल और नवकुण्डीय यज्ञशाला है। यह स्थल एक त्रिवेणी संगम से कम नहीं है, यहां यज्ञ होना बहुत लाभदायक व मंगलदायक होगा। 13 जनवरी तक चलने वाले इस महायज्ञ की तैयारियों ने ट्रस्टी व भक्त जुटे हुए हैं।

हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार करना 'दुखद' : इस्कॉन

कोलकाता/भाभा। कोलकाता स्थित अंतरराष्ट्रीय कृष्णभक्तनामूत संघ (इस्कॉन) ने बृहस्पतिवार को पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा देशद्रोह के मामले में हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार किए जाने को 'दुखद' करार दिया। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने कहा कि मामले की सुनवाई का एकमात्र सकारात्मक पक्ष यह था कि हिंदू संत का प्रतिनिधित्व वकीलों द्वारा किया गया, जो बांग्लादेश की अदालत के समक्ष मामले की पिछली सुनवाई में नहीं किया जा सका था।

राधारमण दास ने कहा, यह दुखद है कि उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। हमें उम्मीद थी कि नव वर्ष में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। बांग्लादेश की एक अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में इस्कॉन के पूर्व संत चिन्मय कृष्ण दास को बृहस्पतिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रवक्ता ने कहा कि चिन्मय कृष्ण दास के वकील बांग्लादेश की उच्च अदालत में अपील करने पर विचार कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि चिन्मय दास की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। दास ने कहा, हमें उम्मीद थी कि इस आधार पर और चूंकि वह पिछले 40 दिन से जेल में हैं इसलिए अदालत उन्हें जमानत दे देगी। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि अगर बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास के लिए अदालत में पेश होने वाले किसी भी वकील की पिटाई या फिर उन्हें धमकी दी जाती है, तो अंतरिम सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चिन्मय कृष्ण दास को बृहस्पतिवार की सुनवाई के लिए अदालत में नहीं लाया गया और उन्हें डिजिटल तरीके से पेश किया गया।

उन्हें 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

विमोचन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



चेन्नई के पुष्करणा भवन में पुष्करणा समाज द्वारा प्रकाशित 'पुष्करणा कैलेंडर 2025' का विमोचन किया गया। इस विशेष अवसर पर संघ के अध्यक्ष महेश पुरोहित, सचिव राज व्यास, सुरेन्द्र व्यास, पंडित बसंत व्यास, प्रवीण व्यास, कैलेंडर चेयरमैन जितेन्द्र बिरसा, बृजमोहन पुरोहित, गोपाल आचार्य और उनकी टीम ने कैलेंडर का विमोचन किया।



मोतीलाल बने श्री व्हीलर फाइनेंसियर क्लब के अध्यक्ष व बांटिया बने मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के श्री व्हीलर फाइनेंसियर क्लब चेन्नई का गठन 1 जनवरी को हुआ जिसमें अध्यक्ष

मोतीलाल ओरतवाल, उपाध्यक्ष सुभाषचंद्र सिंघवी, ज्ञानचंद्र रांका, मंत्री महावीरचंद्र बांटिया, सहमंत्री सुनील कोठारी, कोषाध्यक्ष महेंद्र खींसरा, सलाहकार माणकचंद्र संखलेवा, अमरचंद्र सिसोदिया, एंटरटेनमेंट को-ऑर्डिनेटर संतोष

कोठारी, ग्रीटिंग को-ऑर्डिनेटर विनोद खींसरा के रूप में चयन हुआ। अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया तथा मंत्री ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष ज्ञानचंद्र रांका ने किया।



कमला मेहता को मिला 'सरस्वती पुत्री सम्मान' पुरस्कार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां सैदापेट के एसएस जैन संघ बाजार रोड सदापेट स्थानक के प्रांगण में नववर्ष के आगमन को श्रमण संघीय मधुकर मिश्रीमलजी की आज्ञानवृत्ति साध्वीश्री राजमतीजी, विनयश्रीजी व

जिव्याश्रीजी के सान्निध्य में सजोड़े जाप, प्रवचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंच का संचालन प्रकाशचंद्र बोथरा तथा राजेन्द्र लूंकड़ ने किया।

इस मौके पर साध्वीश्री राजमतीजी की प्रेरणा से सदापेट संघ के पदाधिकारियों एवं गुरु ब्रज मधुकर श्रावक एवं श्राविका समिति के सदस्यों द्वारा कमला सज्जनराज मेहता को सरस्वती

पुत्री सम्मान से सम्मानित किया। अन्य श्रावक श्राविकाओं का संघ द्वारा सम्मान किया गया।

इस मौके पर सज्जनराज मेहता, सिद्धेचंद्र लोढा, रमेश कांकलिया एवं सदस्य सदापेट संघ के ज्ञानचंद्र गांग, रमेशचंद्र गांग, कमलचंद्र छाजेड़, हस्तीमल वेदमुथा, महेंद्र लुणागत, सुशील लूंकड़, लीलम सुराणा, विमल सुराणा उपस्थित थे।

छरीपालित संघ व अन्य तीर्थ यात्रा के लिए खाना हुए 351 यात्री

महावीरस्वामी वर्षीतप चेरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया यात्रा संघ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के महावीर स्वामी वर्षीतप चेरिटेबल ट्रस्ट चामराजपेट के तत्वावधान में आ च ा य श्री अरुणोदयसागरसुरीश्वरजी, अरविंद

सागरसुरीश्वरजी, गणिवर्य श्री अमरपन्नसागरजी, गणिवर्यश्री हीरपन्नसागरजी एवं साध्वीश्री रम्यगुणाश्रीजी की निश्रा में चार दिवसीय सोनगड से शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय गिरिराज छरी पालक यात्रा संघ का आयोजन किया गया है। लाभार्थी वर्षीतप तपस्वी मंजूदेवी मदनलाल बाफना के सहयोग से

बसों द्वारा तलाजा शत्रुंजय डैम तीर्थ, शंखेश्वरजी, चुली तीर्थ, पेपराल तीर्थ, भोराल तीर्थ, भीलडियाजी तीर्थ, नवकार तीर्थ, छाजाल तीर्थ, मणिलक्ष्मी तीर्थ आदि 12 दिवसीय यात्रा संघ का आयोजन किया। इस यात्रा संघ में शामिल होने वाले 351 यात्रियों का यात्रा संघ बेंगलूरु से खाना हुआ।

ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर मेहता ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। इस यात्रा संघ में मंत्री संतोष चौहान, उपाध्यक्ष गौतम मुथा, सहमंत्री महावीर श्रीश्रीमाल, सहकोषाध्यक्ष नरेश बांटिया, ट्रस्ट के प्रवीण पोखवाल सुनील गादिया, किशोर पोखवाल, महेंद्र छाजेड़, गौतम पोखवाल, जयंतीलाल बागरेवा,

उत्तम सालेचा, सुनील मोदी, मोतीलाल बाफना, प्रवेश बालर, सुरेश पिरगल, विकास पालेवा, विशाल पोखवाल एवं वर्षीतप ट्रस्ट के कार्यकर्ता नरेंद्र सोलंकी, महावीर गुलेच्छा, महावीर हुंडिया, महाबल भिलोश, हितेश गुलेच्छा आदि अपनी सेवाएं देंगे। यह जानकारी कैलाश संखलेवा ने दी।

पूजा अर्चना



केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को शिरडी में साईं बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना की।

दकोरिया के राष्ट्रपति ने समर्थकों को जारी किया संदेश, देशविरोधी ताकतों के खिलाफ अंत तक लड़ने का प्रण

सियोल/एपी। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने राजधानी सियोल में अपने आवास के बाहर एकत्र समर्थकों के लिए एक बयान जारी किया जिसमें "देश विरोधी ताकतों के खिलाफ अंत तक लड़ने" का आह्वान किया गया है। येओल ने यह बयान ऐसे वक्त जारी किया है जब कानून प्रवर्तन अधिकारी उन्हें हिरासत में लेने की तैयारी में हैं।

दरअसल येओल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए तीन दिनों के देश में "मार्शल लॉ" लगा दिया था, हालांकि यह ज्यादा देर प्रभावी नहीं रहा लेकिन इसके बाद देश में येओल के खिलाफ माहौल बन गया और सांसद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग करने लगे। उसके बाद येओल महाभियोग का सामना कर रहे हैं।

हलसूर संघ के पदाधिकारियों ने साध्वीश्री शशिप्रभा से किया चातुर्मास निवेदन

बेंगलूरु। स्थानीय श्वेतांबर स्थानकवासि जैन श्रावक संघ हलसूर संघ के संघ अध्यक्ष धनपतराज बोहरा के नेतृत्व में मंत्री अभयकुमार बांटिया, गौतमचंद्र छाजेड़, धनपतराज तातेड, सुनील कावडिया, उममराज मुथा आदि ने तमिलनाडु के बेंगलूरु में विराजित आचार्यश्री पार्श्वचंद्रजी की सुशिक्षा शशिप्रभाजी के दर्शन कर उनसे वर्ष 2025 के लिए चातुर्मास हेतु निवेदन किया। बांटिया ने साध्वियों ने निवेदन किया कि उनके चातुर्मास करवाने के लिए संघ सदस्यों में विशेष उत्साह है और जयगच्छ का 62 वर्षों पश्चात अलसूर में चातुर्मास का सपना साकार होगा। साध्वीश्री शशिप्रभाजी ने कहा कि चातुर्मास स्थल का निर्णय आचार्यश्री होली चातुर्मास पर घोषणा की। इस मौके पर कोलपेट संघ के अध्यक्ष मोहनलाल गडवानी, तमिलनाडु जयमल जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष पारसमल गादिया ने हलसूर संघ का स्वागत किया।



तेयुप विजयनगर ने वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के राजाजीनगर सभागार में उपस्थित साध्वीश्री सिद्धप्रभाजी व कुम्बलगुड स्थित चेतना केन्द्र सभागार में तैरापंथ युवक परिषद विजयनगर द्वारा

प्रकाशित वर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। राजाजीनगर के विमोचन के अवसर पर अभातेयुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मांडोत, विजयनगर सभा अध्यक्ष मंगल कोचर, राजाजीनगर सभा अध्यक्ष अशोक चौधरी, तेयुप राजाजीनगर अध्यक्ष कमलेश चौरडिया, विजयनगर युवक परिषद

प्रबंध मंडल से विकास बांटिया व चेतना केन्द्र में गांधीनगर सभा के अध्यक्ष पारसमल भंसाती, तुलसी चेतना केन्द्र अध्यक्ष अमित नाहटा, तेयुप गांधीनगर अध्यक्ष विमल धारीवाल सहित अनेक पदाधिकारियों ने विमोचन किया। कैलेंडर सहयोगी परिवार के प्रतिनिधियों का विशेष सहयोग

रहा। तेयुप अध्यक्ष कमलेश चौपड़ा ने साध्वियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। तेयुप अध्यक्ष ने सभी प्रायोजक परिवारों का धन्यवाद किया। कैलेंडर के मुद्रण, संकलन में संयोजक राजेश चावत एवं सहसंयोजक श्रेयांस गोलछा का विशेष श्रम रहा।